

bably bailed out this Government and the other Mukherjee ...*(Interruptions)*...

श्री संघ प्रिय गौतम : ये बहुत देर से बोल रहे हैं ।

श्री दीपांकर मुखर्जी : मैं नहीं बोल रहा हूँ । यह मत बोलिए ।

श्री संघ प्रिय गौतम : आप भी तो बोल रहे हैं ।

श्री दीपांकर मुखर्जी : वे मुखर्जी बोल रहे हैं ।

यह बहुत जरूरी है कि हम लोगों का डिसकशन इस पर हो । Don't confuse Pranab Mukherjee with Dipankar Mukherjee. Pranab Mukherjee has bailed out this Government. Sir, what I have stated is that regarding infrastructure, \*rg ^\$a ^^ f fe m CTHT SRT fe+wn

\$fl 'R &l Whatever information that we are having, we are giving to the House. I have gone through all this. There is a very serious situation. In the second para of the reply you say that your FDI js hardly Rs. 5,000 odd crores and your requirement is Rs. 1,60,000 crores. You are talking about private investment. So, this is a serious issue.

MR. CHAIRMAN: All right. We will have a half-an-hour discussion on this question. ...*(Interruptions)*... We have decided that on the basis of this question we will have a half-an-hour discussion.

#### Pesticide Content in Edible Products

\*64. PROF. A LAKSHMI SAGAR:

SHRIMATI KAMLA SINHA:†

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any scientific analysis of various edible products like rice, cereals, fruit, vegetables and animal feed and fodder has been made to know the extent of pesticide content injurious to consumers' health;

(b) if so, the details .thereof, stating the periodicity of such analysis, if any, and the areas where the pesticide content in such products have been found to be the highest; and

(c) the measures taken by Government to ensure the pesticide content at a safe level and to check the unsafe farming

practices in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

(a) and (b) Limited studies from time j to time in different parts of the country were carriud out by Directorate General of Health Services (under Ministry of Health) to assess the level of pesticides, residues in different food articles. The studies revealed that the pesticides residues in most of the edible products like rice, cereals, fruit and vegetables were within the maximum prescribed tolerance limits. No pesticides residues tolerance limits have been prescribed for animal feed and fodder under Prevention of Food Adulteration (PFA) Act, 1954. Some studies in regard to animal feed and fodder have been conducted by ICAR.

(c) (i) The Registration Committee constituted under the Insecticides Act, 1968 prescribes doses and waiting period while approving the use of insecticides on various crops so as to ensure that pesticides residues do not exceed the tolerance limits prescribed under PFA Act, 1954.

(ii) To check unsafe farming practicies, the Government is promoting eco-friend-ly approach through Integrated Pest Man-agement (IPM) on various crops.

(iii) A massive educational and training programme on IPM for farmers and extension functionaries has been launched for minimising the use of pesticides.

(iv) Use of biopesticides including neem based pesticides are being encouraged.

श्री बालकवि बैरागी : यह भी फिर आधे घंटे का हो जाएगा । यह सवाल भी डिसकशन पर आने वाला है ।

सोमपाल : सदन में तो सभी डिसकशन में ही रहता है और क्या होता है ।

**श्रीमती कमला सिन्हा :** सर, में आई आस्क सप्लीमेंट्री ? सदन के पटल में जो उत्तर आया है वह उत्तर संतोषजनक नहीं है।

**श्री बालकवि बैरागी :** सरकार ही संतोषजनक नहीं है।

**श्रीमती कमला सिन्हा :** सर, आपने अगर मेरा प्रश्न देखा होगा तो यह प्रश्न सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। भोजन समग्री से जुड़ा हुआ है। खाद्य पदार्थों और दुग्ध में पेस्टिसाइड्स और डी.डी.टी. वगैरह मिलाए जाते हैं खेती करने में तो उनकी क्या स्थिति है, इसमें पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की ओर से जांच की गयी। इसमें कुछ रिसर्च हुई तो उन्होंने पाया - 9 चावल के सैम्पुल्स की उन्होंने जांच की थी इनके लेविल्स की - कि गामा एच.सी.एच. या आर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड, अनाज बनाने के बाद भी ब्रेकनहीं करते और इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। यहां तक कि एंटोमोलीजी डिपार्टमेंट में जो जांच की गयी उसमें भी पाया गया कि 80 फीसदी से ज्यादा हमारा अनाज, दुग्ध सामग्री और सब्जियां सब में जरूरत से ज्यादा, जो मापदण्ड हैं, उससे कई गुना अधिक से सामग्रियां मिली हुई है। इन केमिकल्स के कारण साइंटिस्ट्स ने देखा की इपीलेप्सी, मिस कैरिजेज, कैंसर, इम्यूनों सिस्टम का डैमेज, किडनी फेल्योर और तरह-तरह की बीमारियां हो रही है। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या विस्तार से इनके बारे में कोई जांच करने की विधि है? क्योंकि इन्होंने जवाब में दिया है - लिमिटेड स्टडीज फ्राम टाइम टु टाइम- रेगुलर स्टडीज नहीं होती है। क्या रेगुलर स्टडीज का कोई इंतजाम करेंगे तत्काल ?

**श्री सोमपाल :** सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मानव स्वास्थ्य, पशुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों के संदर्भ में इसका बहुत महत्व है। यह बात सही है कि जितने भी अध्ययन अभी देश में हुए हैं उनमें यह बात पायी गयी है कि विभिन्न रसायनिक पदार्थों-कीटनाशकों, जेवानाशकों, फंगीनाशकों और वीडिसाइड्स का खरपतवार नाशकों के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा है उसके कारण पूरी खाद्य श्रृंखला में और सब खाद्य पदार्थों में विषैले तत्वों के अवशेष विद्यमान हैं। परंतु जितने अध्ययन भी यहां हुए हैं। उनसे यह पाया गया है कि जो सहनशीलता की सीमा निर्धारित की गयी है। जो मानक निर्धारित किए गए हैं, औसतन वे उनसे कम है। यह खोज खाद्य पदार्थों - चावल, अनाज,

सब्जियां, फल इन सबके संबंध में की गयी है। यह एक बहुत लम्बी सूची है। 71 ऐसे पदार्थों के संबंध में एक ऐसी सीमा का निर्धारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशालाएं इसका परीक्षण कर चुकी है। उन सब में यही पाया गया, केवल एक या दो स्थानों पर ऐसा जरूर है कि जहां निर्धारित सीमा से अधिक विषैले अवशेष पाए गए हैं। परन्तु माननीया सदस्य की यह बात सही है। कि यह प्रयोग, यह जांच नहीं हो रही है और भारत सरकार इस जांच को सारी व्यवस्था को अधिक सशक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना लागू है और इन प्रयोगशालाओं में आधुनिकतम उपकरण ला कर नियमित रूप से जांच करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

#### WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

##### Excess use of Urea by Farmers

\*65. KUMARI NIRMALA DESHPANDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian farmers have been using an overdose of the controlled urea which costs much less than the decontrolled diammonium phosphate and muriate of potash leading to severe imbalance in soil contents;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of fresh initiatives taken/proposed to rectify the imbalance; and

(d) the present status of New Fertiliser Policy and steps proposed for its implementation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) The decontrol of Phosphatic and potassic fertilisers in 1992 resulted in steep rise in their prices leading to their reduced consumption. Consequently the NPK ratio widened from 5.9:2.4:1 (1991-92 pre-decontrol year) to 9.5:3.2:1 (1992-93 post